वैश्विक अर्थव्यवस्था और ढांचा *

दुव्वुरी सुब्बाराव

अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी वित्त मंत्री और मेरे गवर्नर साथी,

1. हाल ही के अप्रत्याशित वैश्विक वित्तीय संकट के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समन्वित रूप से सामना करने के संबंध में अपने प्रयासों में सफल रहने और आर्थिक बहाली की प्रक्रिया के संबंध में रक्षोपाय करने के बाद जी-20 ने अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक असंतुलनों को ठीक करने के और भी अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने की ओर रुख किया है। मजबूत, स्थायी और संतुलित वृद्धि के लिए एक ढांचे के निर्माण के संबंध में जी-20 के सामूहिक प्रयास में भारत को कनाडा के साथ सह-अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पहल की सफलता स्थायी वैश्विक आर्थिक बहाली और बेहतर वैश्विक आर्थिक और वित्तीय अभिशासन के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। इस पहल की सफलता जी-20 की विश्वसनीयता और सामान्य परिस्थितियों में सर्वसम्मति बनाने की इसकी क्षमता के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

2. पिछले नवंबर में सिओल में हुए शिखर सम्मेलन में, जी-20 के नेताओं ने हमें सतत रूप से बड़े असंतुलनों, जिनके संबंध में कार्रवाई अपेक्षित है, की पहचान करने हेतु निर्देशात्मक दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य सौंपा और साथ ही उनके मूल कारणों और समन्वयन की राह में आने वाली अड़चनों का भी पता लगाने को कहा। इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस में हमने यह निर्णय लिया कि हम इस कार्रवाई को समेकित द्वि-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से अंजाम देंगे। प्रथम चरण में, कुछ संकेतकों पर सहमति जताते हुए हमने उन निर्देशात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया जिनके संबंध में सतत रूप से बने हुए बड़े असंतुलनों की पहचान करने के संबंध में अप्रैल माह में आयोजित होने वाली हमारी अगली बैठक तक इनमें से प्रत्येक संकेतक का मूल्यांकन किया जाएगा। अब हमें इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना है और इस कार्रवाई के दूसरे चरण की ओर बढ़ना है। संभवत: इसके फलस्वरूप मूल कारणों, समन्वयन की राह में आने वाली अड़चनों और सुधारात्मक नीतियों और कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित होगा।

3. अब पृष्ठभूमि तैयार हो जाने के पश्चात मैं चार टिप्पणियां करना चाहूंगा।

4. प्रथमत:, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) हमारी कार्रवाई के लिए समय पर तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराने के संबंध में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। निर्देशात्मक दिशानिर्देश बनाने हेतु प्रत्येक निर्देशक के लिए संदर्भ मूल्यों अथवा मानकों का चयन अपेक्षित होता है, साथ ही मानकों अथवा संदर्भ मूल्यों की तुलना में निर्देशकों का मूल्यांकन करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या असंतुलन बड़े हैं। इस कार्य को दो भिन्न कार्य-प्रणालियों अर्थात संरचनात्मक और सांख्यिकीय प्रणालियों का प्रयोग करके अंजाम दिया गया है। आइएमएफ, सैद्धान्तिक सामंजस्य के कारण संरचनात्मक पद्धति को तरजीह देता है क्योंकि अर्थमिति के अनुमानों में एक अंतर्जात अस्थिरता और विरोध होता है जो प्राप्त आंकड़ों से काफी अलग हो सकता है जबकि, फ्रेमवर्क कार्यदल ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है जिसमें इन दोनों ही पद्धतियों को शामिल किया गया है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सांख्यिकीय और संरचनात्मक पद्धतियों के परिणामों के बीच कोई समानता है। यदि नहीं, तो हम इस अंतर से कैसे निपटें।

5. द्वितीयत:, कार्रवाई के प्रथम चरण में प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण देशों के संबंध में लागू मानदंड अधिक सख्त थे। तथापि, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया मुख्यत: यांत्रिक थी, यह प्रमुख रूप से माध्य और माध्यिका के विचलनों पर आधारित थी। तथापि, यह जांचने के लिए कोई भी विश्लेषण नहीं किया गया कि क्या वास्तव में ऐसे विचलनों के चलते बड़े और प्रणालीगत असंतुलन पैदा होते हैं जिनके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। बिना सोचे-समझे अपनाए गए ऐसे यांत्रिक रुख के चलते गड़बड़ियां होंगी। भारत को केस स्टडी मानते हुए मैं दो संभावित गड़बड़ियों के उदाहरण देना चाहूंगा।

6. निजी बचतों के आधार पर स्क्रीनिंग के लिए स्वीकृत मानदंड माध्य से होने वाले बड़े विचलन हैं फिर चाहे संबंधित देश के पास चालू खाते का घाटा अथवा चालू खाता अधिशेष हो और चाहे वह देश आर्थिक विकास के किसी भी चरण में क्यों न हो। यदि हम तर्क की दृष्टि से विचार करें कि ऐसे देश के पास चालू खाते का घाटा है और उसने अपनी निजी बचतों को कम कर दिया है तो उसे अपने चालू खाते के घाटे को बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद बाह्य असंतुलन संकेतकों के द्वारा इसकी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। उदाहरणार्थ भारत में हमारा विकास मुख्य रूप से घरेलू बचतों के कारण हुआ है। यदि पारस्परिक आकलन प्रक्रिया के कारण, भारत से घरेलू बचतों को कम करने के लिए कहा जाए तो इसके फलस्वरूप विदेशी बचतों पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी और वास्तव में इससे असंतुलन बढ़ेगा। वास्तव में यह विरोधाभास की स्थिति होगी।

*डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जी-20 के मंत्री समूह की बैठक में वाशिंगटन डीसी में 15 अप्रैल, 2011 को दिया गया भाषण।

7. दूसरा उदाहरण है सार्वजनिक ऋण संबंधी व्यवहार। माध्य/माध्यिका में होने वाले विचलनों के विपरीत विकसित देशों के लिए उच्च प्रारंभिक सीमा रखे जाने के साथ विकसित और विकासशील देशों के संबंध में विषम संदर्भ मूल्यों में होने वाले विचलनों को रखे जाने का प्रयास किया गया था। ये प्रारंभिक सीमाएं पहले की प्रारंभिक सीमाओं के औसत पर आधारित हैं, न कि अपेक्षित अथवा अनुमानित वृद्धि दरों से संबंधित ऋण निरंतरता के वर्तमान अनुमानों के आधार पर। ऋण को स्थिरता प्रदान करने हेतु समायोजन अवधि भी काफी बाद की रखी गयी है। वर्ष 2030 की अवधि काफी लंबी अवधि है और यदि मैं लॉर्ड कीन्स के अमर शब्दों का उद्धरण दूं तो हममें से बहुत से लोग तब तक जीवित नहीं बचेंगे। विकसित देशों में राजकोषीय संतुलन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इतना आवश्यक क्यों है इसका एक कारण यह है कि, आरक्षित निधियों को जारी करने वाले देश होने कारण उनके घाटों का बड़े स्तर पर स्पिलओवर प्रभाव पड़ता है।

8. यहां दो मुद्दे हैं। पहला विकसित देशों और उदीयमान और विकासशील देशों के लिए जीडीपी की तुलना में ऋण के अलग-अलग अनुपात का उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि हम भविष्योन्मुखी रुख अपनाएं तो यह बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होगा कि ईएमडीसी को सार्वजनिक ऋण बढ़ाना होगा ताकि वे अपने विकास संबंधी कार्यों का वित्तपोषण कर सकें और सापेक्ष संदर्भ में जीडीपी की तुलना में उनके सार्वजनिक ऋण का अनुपात विकसित देशों की तुलना में उच्च होना जरूरी होगा। दूसरी बात यह कि देशों की ऋण निरंतरता को कुछ वैश्विक मानकों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि इसे अलग-अलग देशों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। देश किस सीमा तक उच्च वृद्धि के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने हेतु वित्त की व्यवस्था कर पाएंगे, इस बात का आकलन किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऋण की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, हमारा सार्वजनिक ऋण प्रमुख रूप से घरेलू है और इसीलिए सार्वजनिक ऋण के कारण वैश्विक प्रणालीगत असंतुलनों को प्रभावित करने की भारत की क्षमता यदि शून्य नहीं तो नगण्य है।

9. तीसरी टिप्पणी जो मैं करना चाहता हूँ उसका संबंध इस बात से है कि हम अपने नेताओं के इरादों का क्या अभिप्राय लेते हैं जिन्हें निरंतर बने हुए बड़े असंतुलनों पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या दूसरे चरण में बड़े असंतुलनों की ओर ध्यान देकर हमें अपनी ऊर्जा नष्ट कर देनी चाहिए या इसके बजाए केवल प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बड़े असंतुलनों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनके महत्त्वपूर्ण स्पिलओवर प्रभाव पड़ते हैं। क्या प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बड़े असंतुलनों की साधारण सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से पहचान कर पाना बहुत कठिन है, जैसे कि कुल असंतुलनों अथवा वैश्विक जीडीपी के अनुपात के रूप में देश संबंधी असंतुलन? इस तरह से हम सतत रूप से चले आ रहे बड़े असंतुलनों के मूल कारणों पर और हमारे नेताओं द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उनके समायोजन में आने वाली बाधाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

10. अब मैं अपनी चौथी और अंतिम टिप्पणी दूंगा। एक प्रश्न उठता है कि क्या फ्रेमवर्क कार्रवाई को देशों के केवल निवल असंतुलनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए अथवा स्थिति के अनुसार अंतर्देशीय या अंतर-क्षेत्रीय असंतुलनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे मन में एक महत्त्वपूर्ण जो प्रश्न उठ रहा है, वह यह नहीं है कि क्या असंतुलन आंतरिक है अथवा बाह्य, अथवा सकल है या निवल, बल्कि यह कि क्या संबंधित असंतुलन व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण बाह्य स्पिलओवरों को निर्मित करता है अथवा इसमें ऐसी स्थिति निर्मित करने की क्षमता है।

11. निष्कर्ष के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा एक प्रभावी परिणाम आना चाहिए जिससे यह संकेत मिल सके कि जी-20 आगे अर्थव्यवस्था के लिए न केवल मजबूत, स्थायी और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के प्रति गंभीर है बल्कि इस तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचनात्मक समस्याओं को सुलझाने के संबंध में एक प्रभावी और प्रासंगिक संस्था है और रहेगी। धन्यवाद।